EDITORIAL

"Disappointment of the Past Year vs. Hope in the New Year."

The year of disappointment is coming to an end on December 31, 2025. At the beginning of this year, a ray of hope emerged among BSNL employees that the BSNL management and the central government would prioritize their problems and bring smiles on the faces of disappointed employees. Instead, the year passed with employees counting each day, hoping that better days would come.

A Third Pay Revision Committee was formed, which met continuously, but an agreement remained elusive as the management side failed to reach a consensus. Seeing this, employees began to pressure their union leadership. This resentment eventually shifted from the management toward the labor unions themselves. The management cunningly tried to create a situation where employees would lose faith in their own unions, propagating the narrative that the pay revision was stalled due to a lack of cooperation from union representatives.

The truth was that the pay scale proposed by the management was very small, and accepting it would have meant employees facing a pay freeze for another 4-5 years. Union representatives fought to correct this, but the management remained adamant. Ultimately, the union leadership took a tough stand and demanded a written guarantee that whatever is decided regarding the fitment formula and other allowances for executive officers would also be applicable to non-executive employees.

On October 8, 2025, the management gave this written guarantee and signed the agreement for the Third Pay Revision for non-executive employees. This reignited hope among employees; however, under a short-sighted and cunning policy, the management has since proceeded at a snail's pace.

It is noted that by the end of 2025, nearly three months will have passed since the agreement, yet the management has not had the agreement approved by the BSNL Board. This has caused deep discontent among all officers and employees, which is now turning into anger.

In this situation, a meeting of the General Secretaries of officer and employee unions / associations was held on December 18, 2025, where the management's anti-employee policies were strongly condemned. The management was warned that if the pay revision file is not approved by the BSNL Board and forwarded to the Department of Telecommunications (DoT) by the end of the year, a period of unrest will begin in BSNL from the start of 2026.

On December 30, 2025, a memorandum signed by all organizations was submitted to the Chairman and Managing Director (CMD) of BSNL, stating that on January 8, 2026, all BSNL officers and employees would hold a protest during lunch hours. If demands are still not met, a one-day dharna (protest) will be organized at Jantar Mantar, Delhi, on February 20, 2026.

The revenue of BSNL continues to decline due to the inefficient policies of the top management. For the past month, the communication infrastructure has been failing, affecting mobile and

FTTH services and causing heavy revenue loss. No investigation has been launched by the government against the high-ranking officers responsible for this "crime." Employees believe that the government is running this massive, vital company by making temporary appointments to the post of CMD for short durations (3-6 months), which seems inadequate for managing such a large enterprise.

The proverb "Nero fiddled while Rome burned" is becoming a reality here. In this dire situation, the future of employees looks dark. Facilities for BSNL employees are being snatched away one by one. Whenever the employees raise their voices, they are told the company's financial health is not good. However, due to the management's dictatorial attitude, the company is losing hundreds of crores in revenue. Now, employees have no choice but to move forward on the path of a united struggle.

History is witness that since the British era, workers have resolved their issues by fighting against those in power. Employees of public sector undertakings (PSUs) give priority to the industry and cooperate fully for its strength. BSNL employees also contribute to the company's strength with their sweat and blood. BSNL is a company of public interest, and implementing the government's telecom policies is its priority.

While the top management creates policies and targets, it is the middle-management and non-executive employees who implement them on the ground. Due to the management's arbitrary attitude, it is becoming difficult to achieve these targets. Yet, the management blames the employees for these failures and deprives them of their benefits. This is an absolute injustice.

While private companies have been providing high-tech services like 4G since 2012, BSNL is still unable to provide these services fully in 2025. On one hand, BSNL management works through high-tech based services using external contractors who employ unskilled labor, affecting service quality. On the other hand, skilled and hardworking employees are assigned tasks where no significant achievement is possible. If an honest assessment is made, the decline of the company and the loss of revenue are solely due to government policies and the short-sightedness of top management.

Despite these difficult circumstances, we welcome the New Year and urge all fellow employees to work with new zeal and enthusiasm. At the same time, we must stand united against the management's wrong policies, inefficiency, and irresponsible actions. Participate in the protest programs determined by the leadership with full awareness to secure your future and protect BSNL.

Long Live NFTE – Long Live Employee & Unity

संपादकीय

बीते वर्ष की नाउम्मीदी बनाम नए वर्ष में उम्मीद

नाउम्मीदी की एक वर्ष 31 दिसंबर 2025 को पूर्ण होने जा रहा है। इस वर्ष के आरंभ में बीएसएनएल के कर्मचारियों के बीच एक आशा और उम्मीद का संचार हुआ था कि उनके लिए उनके समस्याओं को बीएसएनएल प्रबंधन एवं केंद्र सरकार प्राथमिकता देगी और मायूस कर्मचारियों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी परंतु जाने वाला साल कर्मचारियों की मायूसी को समाप्त नहीं कर पाया। अपितु कर्मचारी विवश होकर एक–एक दिन की गिनती करते रहे कि अब हमारे लिए अच्छे दिन आएगे। तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति गठित की गई थी जिसकी बैठक लगातार चल रही थी परंतु समझौते के नजदीक कर्मचारी पक्ष और प्रबंधन पक्ष नहीं पहुंचे रहे थे। इस स्थिति के जारी रहने पर कर्मचारी अपने संगठन के नेतृत्व पर दबाव डालने लगे की वेतन पुनरीक्षण के लिए समझौता में विलंब न किया जाए और कर्मचारियों का आक्रोश प्रबंधन के प्रति न होकर श्रमिक संगठनों के प्रति उजागर होने लगा। प्रबंधन पक्ष बहुत ही कुटिलता के साथ यह स्थिति लाना चाह रही थी ताकि कर्मचारी गण अपने संगठन के प्रति उदासीन होते जाएं और प्रबंधन यह प्रचारित कर सके की श्रमिक सघों के प्रतिनिधियों के असहयोग के कारण वेतन पुनरीक्षण समिति का निर्णय बाधित हो रहा है। सत्यता यह थी कि प्रबंधन पक्ष ने कर्मचारियों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किया था वह बहुत ही छोटे आकार का था और इस वेतनमान के लागू होने पर पूर्व से ही वेतन में ठहराव को झेल रहे कर्मचारियों को नए वेतनमान के लागू होने पर भी चार–पांच वर्षो के अंदर वेतन ठहराव का सामना करना पड़ेगा। श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे परतु प्रबंधन पक्ष अपने दृष्टकोण पर अडिग रहा। खासकर श्रमिक संगठन के लोग केनीया वजूद भी इनके वेतनमान में वांछित सुधार नहीं किया गया। फिटमेंट फार्मूले तथा अन्य भते पर भी गतिरोध जारी रहा। अतत कर्मचारी संगठन के नेतृत्व के लोगों ने विवश होकर बीच का रास्ता निकाला और इन दो मुद्दों पर लिखित गारंटी मांगी कि जो फिटमेंट फार्मूला तथा अन्य भते के सबंध में कार्यपालक अधिकारियों के लिए निर्णय लिया जाएगा उसे नन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए भी लागू की जाएगी। प्रबंधन पक्ष ने ऐसा लिखित गारंटी दिया और इसके साथ ही 8 अक्टूबर 2025 को नन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए तृतीय वेतन पुनरीक्षण के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। इस समझौते के उपरांत पुनः एक बार कर्मचारियों में उत्साह की लहर फैल गई तथा उन्हे एक रजत रेखा दिखलाई देने लगा कि उच्च प्रबंधन एवं सरकार अब वेतन निर्धारण का कार्य शीघ्रता से संपन्न करेगी परंतु अदूरदर्शी एवं कुटिल नियत के तहत प्रबंधन ने कछुए की गति से कार्रवाई शुरू की है।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2025 के समाप्त होने तक समझौते का लगभग तीन महीने हो जाएंगे परंतु अभी तक प्रबंधन ने बीएसएनएल बोर्ड से समझौते की संचिका को अनुमोदित नहीं कराया है। जिससे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त है, जो आक्रोश में परिवर्तित हो रहा है। इस परिस्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी संगठनों के महामंत्रियों की एक बैठक दिनांक 18 दिसंबर 2025 को हुई, जिसमें प्रबंधन के कर्मचारी विरोधी नीतियों की घोर निंदा की गई तथा प्रबंधन को सचेत किया गया कि अगर वर्षात तक अगर प्रबंधन वेतन निर्धारण समझौते की संचिका का बीएसएनएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कराकर दूरसंचार विभाग को अग्रसारित नहीं करती है तो नया वर्ष 2026 के आरंभसे ही बीएसएनएल महकमें में अशांति की दौर की शुरुआत होगी। 30 दिसंबर 2025 की संध्या सभी संगठनों के महामंत्रियों के हस्ताक्षर से बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को ज्ञापन दिया गया की 8 जनवरी 2026 को बीएसएनएल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के सगठन के सदस्य भोजन अवकाश के समय प्रदर्शन करेंगे और इसके बावजूद मिइतनंल भी मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 फरवरी 2026 को दिल्ली के जतर मंतर में एक दिवसीय धरना एवं आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि अकर्मण्य उच्च प्रबंधन के अदूरदर्शी नीतियों के कारण बीएसएनएल के राजस्व में गिरावट बदस्तूर जारी है। पिछले दिनों लगभग एक महीने तक सचार आधारसेवा ठप रही, जिससे बीएसएनएल की मोबाइल सेवाए, एफ टी टी

एच सेवाएं प्रभावित होती रही और राजस्व की भारी क्षति होती रही। परंतु इस घोर अपराध के लिए सरकार की ओर से जांच कर प्रबंधन के उच्च पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। कर्मचारी यह मानने लगे हैं कि सरकार ने अस्थाई अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद पर अल्पकालिक नियुक्ति दे कर और कभी छः महीने कभी तीन महीने का सेवा विस्तार दे कर इस कंपनी का संचालन करा रही है, जो इस विशालकाय, महत्वपूर्ण कपनी के संचालन में सक्षम प्रतीत नहीं हो रहे हैं। यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि रोम जलता रहा और नीरो बंशी बजाता रहा। इस विषम परिस्थिति में कर्मचारियों का भविष्य अधकारमय होते जा रहा है। ऐसा इसलिए कि बीएसएनएल कर्मचारियों की समस्त सुविधाए शनैः शनैः समाप्त कर दी गई है। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कोई भी सवाल उठाने पर कहा जाता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है, इसलिए आर्थिक मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है। परंतु उच्च प्रबंधन के तानाशाही रवैए के कारण एक झटके में कंपनी को सैकड़ों करोड़ की राजस्व की क्षति हो रही है। अब कर्मचारियों के सामने पूर्ण एकजुटता के साथ आंदोलन के पथ पर अग्रसर होने के सिवा कोई विकल्प नहीं बच जाता है।

इतिहास साक्षी है कि ब्रिटिश शासनकाल से ही कामगारों ने सता से लड़कर ही अपने समस्याओं का निराकरण कराया है। वर्तमान परिपेक्ष में लोक उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी एवं उनकी संगठनों की सोच के अनुसार के संगठन नेतृत्व उद्योग को प्राथमिकता देते हैं और जिस उपक्रम में कार्य करते हैं। उस उपक्रम की सुदृढता के लिए हर संभव सहयोग करते हैं। बीएसएनल के कार्यरत कर्मचारी भी अपना खून पसीना देकर कंपनी की सुदृढ़ता में योगदान करते हैं। यह कंपनी लोकहित कंपनी है और सरकार की दूरसंचार नीतिर्यो को लागू करना इस कंपनी की प्राथमिकता है।

ज्ञातव्य है कि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कपनी की उच्च प्रबंधन कार्य तालिका बनाती है और मध्यवर्गीय अधिकारी एवं नॉन एक्जीक्यूटिव कर्मचारी उसे सर–जमीन पर उतारते हैं। नीतियों की खामी तथा उच्च प्रबंधन की मनमाने रवैया के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई होती है। परतु उच्च प्रबंधन में बैठे अधिकारी इस असफलता के लिए कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए उनको मिलने वाले सुविधाओं से वंचित करते हैं। यह सर्वथा अन्याय की श्रेणी में आता है। बीएसएनएल कंपनी को बहुत बड़े प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है। एक तरफ निजी कंपनिया वर्ष 2012 से ही उच्च तकनीक जैसे 4जी आधारित सेवाएं दे रही हैं परतु बीएसएनएल वर्ष 2025 में भी पूर्ण रूप से यह सेवा नहीं दे पा रही है। एक तरफ बीएसएनएल प्रबंधन उच्च तकनीक पर आधारित सेवाओं के लिए बाहरी ठेकेदारों द्वारा कार्य करा रही है, जो अकुशल मजदूरों से कार्य लेते हैं, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। दूसरी तरफ अपने दक्ष एवं कर्मठ कर्मचारियों को ऐसे कार्य में लगाती है, जहां कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती। बीएसएनएल के कर्मचारी कपनी के प्रति पूर्ण वफादारी के साथ कार्य करते हैं परंतु बाह्य स्त्रोत से लगाए गए ठेकेदार अपने मुनाफा के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर सही आकलन किया जाए तो कंपनी में गिरावट और राजस्व में क्षति के लिए सरकार की नीतियां एवं उच्च प्रबंधन की अदूरदर्शिता ही कारण है।

इन सारे विषम परिस्थितिर्या के बावजूद हम नव वर्ष का स्वागत करते हैं तथा अपने समस्त कर्मचारी साथियों से आग्रह करते हैं कि नए वर्ष में नई जोश और नई उमंग के साथ निष्ठा पूर्वक कंपनी के कार्य को करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण एकजुटता के साथ प्रबंधन की गलत नीतियों, अकर्मण्यता, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई का पर्दाफाश करें और अपनी मांगों के प्रति पूर्ण जागरूकता के साथ शीर्ष संगठन द्वारा निर्धारित आंदोलनात्मक कार्यक्रम में भाग लेकर अपना भविष्य सुरक्षित करें तथा बीएसएनएल की सुरक्षा करें।

एन एफ टी ई जिंदाबाद – कर्मचारी एकता जिंदाबाद